

दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्व का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजित करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।



RNI NO - CHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शनिवार 27 नवंबर 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-04, अंक- 60

महत्वपूर्ण एवं खास

ब्रिटेन ने छह दक्षिण अफ्रीकी देशों की उड़ान पर लगाया प्रतिबंध

लंदन। ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीकी देशों में कोरोना वायरस (कोविड-19) के नये स्ट्रेन के प्रसार को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, लेसोथो, इस्वातिनी, जिम्बाब्वे और नामीबिया के लिए 28 नवंबर तक उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यहां जारी एक बयान में कहा, अपराह शुक्रवार 26 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, लेसोथो, इस्वातिनी, जिम्बाब्वे और नामीबिया को ब्रिटेन की यात्रा लाल सूची में शामिल किया जाएगा। इन छह देशों से सीधी उड़ानें शुक्रवार दोपहर से 28 नवंबर तक प्रतिबंधित रहेंगी। बयान के अनुसार शुक्रवार से गैर ब्रिटेन और आयरिश नागरिक जिन्होंने पिछले 10 दिनों में इन छह अफ्रीकी देशों की यात्रा की है के ब्रिटेन में प्रवेश की मनाही होगी। जबकि ब्रिटेन और आयरिश नागरिकों को 10 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। उल्लेखनीय है कि इस सप्ताह की शुरुआत में ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बोत्सवाना में कोरोना वायरस के नये स्ट्रेन पाये जाने को लेकर चिंता जतायी थी। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय संचारक रोग संस्थान ने बाद में 22 मामलों की पुष्टि भी की थी।

कोयला खदान में लगी भीषण आग में 52 लोगों की दर्दनाक मौत

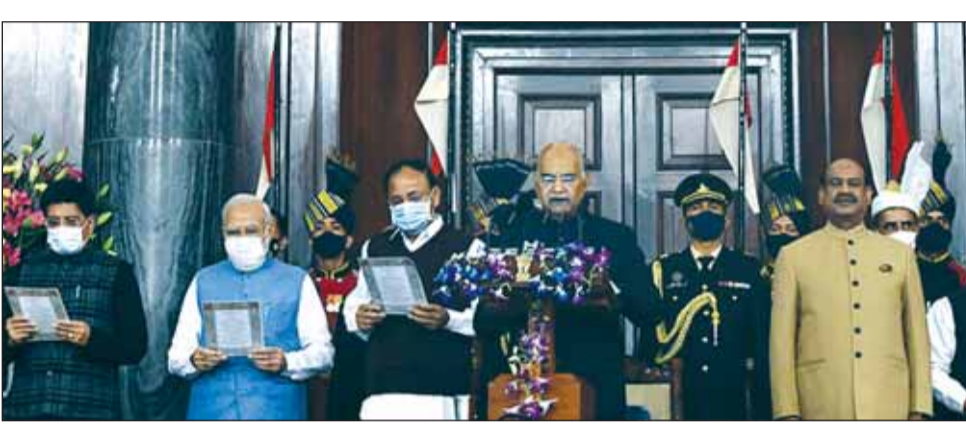
मास्को। रूस के साइबेरिया में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक कोयला खदान में आग लगने से 52 लोगों की मौत हो गई जिसमें छह बचावकर्मी भी शामिल हैं। इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि खदान में 14 शव मिले हैं। घटना गुरुवार को हुई है। यह देश में पांच साल में सबसे घातक खदान दुर्घटना मानी जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि लिस्टव्यजनाया कोयला खदान में कोई भी जीवित व्यक्ति का रेस्क्यू करने का मौका नहीं मिला। कई शव अब भी अंदर ही हैं, जिन्हें सतह तक लाकर बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले खबर मिली थी कि कोयले के धुएं के कारण वेन्टिलेशन की दिक्रत से 11 खनिकों की मौत हो गई है। जो 250 मीटर की गहराई पर काम कर रहे थे। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि 38 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से चार की हालत गंभीर है और 13 अन्य लोगों का बिना भर्ती किए उपचार किया गया है। दुर्घटना के समय 285 लोग अंडरग्राउंड काम कर रहे थे और उनमें से अधिकांश को शुरुआत में ही खदान से बाहर निकाल लिया गया था। कोयला खदान की घटना की बात करें, तो ये आग तेज धमाका होने के बाद लगी थी। ये धमाका अचानक हुआ, जिसके चलते बहुत से लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। बचावकर्मी और पुलिस घटना की सूचना मिलते ही यहां पहुंच गए थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी 'गहरी संवेदना' व्यक्त की है। वहीं केमेरोवो क्षेत्र ने शुक्रवार से रिवार तक तीन दिनों के शोक की घोषणा की है।

श्रीलंका में भारी बारिश से 14 लोगों की मौत

कोलंबो। श्रीलंका में पिछले सप्ताह से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश जारी है, जिससे 14 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति के लापता होने की खबर है। यह जानकारी आपदा प्रबंधन केंद्र (डीएमसी) ने दी। डीएमसी के नए आंकड़ों के अनुसार, 9 जिलों में प्रतिकूल मौसम की वजह से 100,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं, जबकि 114 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। केंद्र ने यह भी कहा कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में 22 लोग घायल हुए हैं। श्रीलंका के मौसम विभाग ने गुरुवार को कहा कि 19 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि 19 जिलों में 100 मिमी से ज्यादा भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि श्रीलंका के दक्षिण-पूर्व और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में प्रचलित निम्न-स्तर के वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया था, जो कम दबाव के विक्षोभ में विकसित हुआ और वर्तमान में देश के पूर्व में स्थित था। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम की स्थिति खराब होने की उम्मीद है, लेकिन कम वायुमंडलीय विक्षोभ के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है।

भारत ने लिखी है लोकतांत्रिक विकास की अद्भुत गाथा : कोविंद

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय संविधान की 72 वीं वर्षगांठ के मौके पर संसद के केन्द्रीय कक्ष में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में संविधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि 72 साल पहले इसी सेंट्रल हॉल में हमारे संविधान निर्माताओं ने इस दस्तावेज को भारत के सुनहरे भविष्य के लिए स्वीकार किया था। करीब सात दशक की छोटी सी समयवधि में ही भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक विकास की अद्भुत गाथा लिख दी है। इसने पूरी दुनिया को चकित कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं यह मानता हूँ कि भारत की यह विकास यात्रा, हमारे संविधान के बल पर ही आगे बढ़ती रही है।



उपलब्धि के लिए हम संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और जन-गण-मन की बुद्धिमत्ता को नमन करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे संविधान में वे सभी उदात्त आदर्श समाहित हैं जिनके लिए दुनिया के लोग भारत की ओर सम्मान और आशा भरी दृष्टि से देखते रहे हैं। उन्होंने कहा कि 'हम भारत के लोग' इन शब्दों से आरम्भ होने वाले हमारे संविधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत का संविधान लोगों की आकांक्षाओं की सामूहिक

अभिव्यक्ति है। हमसे अन्य लोकतंत्रों ने बहुत कुछ सीखा- राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में न केवल महिलाओं को आरम्भ से ही मताधिकार प्रदान किया गया बल्कि कई महिलाएं संविधान सभा की सदस्य थीं और उन्होंने संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। पश्चिम के कुछ विद्वान कहते थे कि भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था विफल हो जाएगी। परन्तु यह प्रयोग न केवल

सफल रहा, अपितु समय के साथ और मजबूत हुआ है। यहां तक कि अन्य लोकतंत्रों ने भी इससे बहुत कुछ सीखा है। राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि आज संविधान सभा की चर्चाओं तथा संविधान के कैलेंडरिफेज वर्जन और अद्यतन संविधान के डिजिटल संस्करण जारी कर दिए गए हैं। इस प्रकार, टेक्नॉलॉजी की सहायता से, ये सभी अमूल्य दस्तावेज सबके लिए सुलभ हो गए हैं।

संविधान की प्रस्तावना का हुआ पाठ- संबोधन से पहले राष्ट्रपति कोविंद ने संविधान बनाने वाली संविधान सभा की चर्चाओं के डिजिटल संस्करण को भी जारी किया। उन्होंने संविधान की मूल प्रति का डिजिटल संस्करण अद्यतन संविधान भी जारी किया। इसके अलावा उन्होंने संविधान पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी पोर्टल का शुभारंभ भी किया। संबोधन समाप्त होने के बाद उन्होंने संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया और केन्द्रीय कक्ष में मौजूद सभी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इसके अलावा एक विशेष पोर्टल के जरिये देश भर में अपनी अपनी जगह से करोड़ों लोगों ने संविधान सभा की प्रस्तावना का पाठ किया। इसके लिए सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में विशेष इंतजाम किये गये थे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के बहिष्कार पर किया कटाक्ष- संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेंट्रल

हॉल में अपना संबोधन दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत राष्ट्रपति महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए की। इस मौके पर उन्होंने विपक्षी पार्टी के शामिल नहीं होने पर प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यह विरोध आज से नहीं हो रहा है। उन्होंने पारिवारिक पार्टियां कहकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई दल अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रहा है, जो संविधान को सम्पत्ति लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है और वो है पारिवारिक पार्टियां। उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर एक परिवार से एक से अधिक लोग जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन एक पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में है।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर से शुरू होने की संभावना

चीन, यूके, जर्मनी समेत 14 देशों पर जारी रहेगा प्रतिबंध

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को नियमित करने का फैसला किया है। हालांकि 14 देशों के लिए उड़ान अभी भी संभव नहीं है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए इन 14 देशों के लिए उड़ानों की अनुमति नहीं दी गई है। प्रतिबंधित देशों की लिस्ट में यूरोपीय संघ और कुछ अन्य देश भी शामिल हैं जहां कोरोना के नए संस्करण का पता चला है। सरकार की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि इस साल के अंत तक कोविड की वजह से उड़ानों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। इस मामले की जानकारी

रखने वाले लोगों ने शुक्रवार को बताया कि इस लिस्ट में जिन देशों को शामिल नहीं किया गया है उनमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर शामिल हैं। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध मार्च 2020 से लागू है। हालांकि, जिन देशों में कोरोना महामारी का प्रकोप कम हुआ है वहां के लिए फिर से उड़ाने चालू की गई हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पर्यटन उद्योग भी सरकार पर उड़ानों से प्रतिबंध हटाने का दबाव बना रही है। पर्यटन उद्योग ने उन देशों के लिए उड़ानें शुरू करने का अनुरोध किया है जहां कोरोना नियंत्रण में है।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर बेहद खराब श्रेणी में पहुंची

नई दिल्ली (आरएनएस)। सिस्टम ऑफ एयर चालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) के अनुमानों के मुताबिक हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 प्रदूषकों के संतोषजनक से मध्यम स्तर की रिकॉर्डिंग के एक दिन बाद, दिल्ली-एनसीआर ने समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 380 दर्ज किया, जिसमें दोनों प्रदूषक फिर से बहुत खराब श्रेणी में आ गए।



एनसीटी पर हवा की गुणवत्ता 26 नवंबर को बहुत खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। रात के दौरान ज्यादातर शांत या धीमी हवाएं प्रभावी फैलाव के लिए प्रतिकूल होती हैं। वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार होने की संभावना है, लेकिन 27 नवंबर और 28 नवंबर को बहुत खराब श्रेणी में

रहने की संभावना है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। 27 नवंबर से 30 नवंबर तक धीरे-धीरे सुधार होने की संभावना है और पीएम2.5 प्रमुख प्रदूषक होगा। प्रमुख सतही हवा दिल्ली के दक्षिणपूर्व-पूर्वी दिशा से 6 किमी प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आने की संभावना है, मुख्य रूप से 27 नवंबर को सुबह साफ आसमान और कोहरा रहेगा। प्रमुख सतही हवा अलग-अलग दिशाओं से आने की संभावना है। दिल्ली में 6 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 28 नवंबर को मुख्य रूप से साफ आसमान और सुबह हल्का कोहरा रहेगा। 29 और 30 नवंबर के दौरान हवाएं अपेक्षाकृत तेज होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार की सुबह धुंध के साथ मुख्य रूप से साफ आसमान की भविष्यवाणी की। दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र और राकेश अस्थाना को नोटिस

दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति के खिलाफ याचिका

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया जिसमें गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा गया था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपापा की बेंच ने केंद्र सरकार और राकेश अस्थाना को नोटिस जारी किया और



एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटेरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की याचिका पर उनसे दो सप्ताह में जवाब मांगा है। एनजीओ ने 31 जुलाई को अपनी रिटायरमेंट से चार दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ एक रिट याचिका और अपील दायर की है।

एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 18 नवंबर के निर्देश के अनुसार अपील दायर की है। इस दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अस्थाना का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वे दो सप्ताह में अपना

जवाब दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को एनजीओ से दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने को कहा था। 12 अक्टूबर को, दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा था कि उनके चयन में कोई अनियमितता या कमी नहीं थी। बता दें कि, 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी अस्थाना, जो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे, उन्हें एक साल के कार्यकाल के लिए गुजरात कैडर से केंद्र शासित प्रदेश कैडर में स्थानांतरित किए जाने के बाद 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था।

बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्य

नीति आयोग की रिपोर्ट : कई प्रदेशों में सबसे कम गरीबी

नई दिल्ली (आरएनएस)। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्यों के रूप में उभरे हैं। सूचकांक के अनुसार, बिहार की 51.91 प्रतिशत जनसंख्या गरीब है, इसके बाद झारखंड में 42.16 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 37.79 प्रतिशत लोग गरीब हैं। सूचकांक में मध्य प्रदेश (36.65 प्रतिशत) को चौथे स्थान पर रखा गया है, जबकि मेघालय (32.67 प्रतिशत) पांचवें स्थान पर है।



इन राज्यों में सबसे कम गरीबी - केरल (0.71 प्रतिशत), गोवा (3.76 प्रतिशत), सिक्किम (3.82 प्रतिशत), तमिलनाडु (4.89 प्रतिशत) और पंजाब (5.59 प्रतिशत) सूचकांक के साथ पूरे भारत में सबसे कम गरीबी दर्ज की है। ये

राज्य सूचकांक में सबसे नीचे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत का राष्ट्रीय एमपीआई का मानक, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (ओपीएचआई) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा विकसित विश्व स्तर

पर स्वीकृत और मजबूत कार्यप्रणाली का उपयोग करता है। केंद्रशासित प्रदेशों में पुडुचेरी में सबसे कम गरीब - जबकि केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा और नगर हवेली (27.36 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर व लद्दाख (12.58), दमन और दीव (6.82 प्रतिशत) और चंडीगढ़ (5.97 प्रतिशत) सबसे गरीब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभरे हैं। पुडुचेरी में 1.72 प्रतिशत आबादी ही गरीब है, जबकि लक्षद्वीप में 1.82 प्रतिशत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 4.30 प्रतिशत और दिल्ली में 4.79 प्रतिशत गरीब हैं। भारत के एमपीआई में तीन आयाम - रिपोर्ट में कहा गया है कि

महत्वपूर्ण रूप से यह सूचकांक परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले कई अभावों को दर्ज करता है। इसमें कहा गया है कि भारत के एमपीआई में तीन समान आयाम हैं- स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, प्रसवपूर्व देखभाल, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते जैसे 12 संकेतकों द्वारा दर्शाए जाते हैं। 2015 में 193 देशों द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) ढांचे ने दुनिया भर में विकास की प्रगति को मापने के लिए विकास नीतियों, सरकारी

प्राथमिकताओं और मैट्रिक्स को फिर से परिभाषित किया है। 17 वैश्विक लक्ष्यों और 169 लक्ष्यों के साथ एसडीजी ढांचा अपने पूर्ववर्ती मिलेनियम डेवलपमेंट गोलस (एमडीजी) की तुलना में काफी व्यापक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अपने प्रस्ताव में कहा कि भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विकसित होना एक सार्वजनिक नीति उपकरण स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है जो बहुआयामी गरीबी की निगरानी करता है, साक्ष्य-आधारित और केंद्रित हस्तक्षेपों के बारे में सूचित करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी पीछे रह गया है।